

कालापीपल में सीएम मोहन का ग्रैंड रोड शो

● कई रेलवे ओवर ब्रिज और नई सड़कों की घोषणा ● डॉ. यादव ने कहा- इसी महीने लागू होगा यूसीसी किसानों को अब साल में एक बार चुकाना होगा लोन



भोपाल। सीएम मोहन यादव ने शाजापुर के कालापीपल को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 30.86 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही सीएम ने वहां रोड शो किया है और किसानों को संबोधित किया है। सीएम मोहन यादव ने शाजापुर को नई सड़कें और रेलवे ओवर ब्रिज देने की घोषणा की।

किसानों को छह-छह महीने के ब्याज से दी मुक्ति- उन्होंने कहा कि जो धरती को हरियाली का उपहार देते हैं, वही आने वाले कल को आकार देते हैं।

किसान मुस्कुराए तो मुस्कुराता जहां है, इन्हीं की मेहनत से महकता अपना हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा कि किसानों का 6-6 महीने के ब्याज का झंझट खत्म हो जाएगा। अब हम एक

साल के लिए लोन देंगे। किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि आपको परेशानी क्या है। आप बताइए नर्मदा कहां और शाजापुर कहां। फिर भी, यहां के 118 गांवों में नर्मदा जल आता है। आने वाले दिनों में जो-जो गांव बचे हैं, वहां भी पानी देंगे, पूरे क्षेत्र में पानी देंगे।

कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने पापों के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। किसान को भगवान के समान पूजने के काम, अगर कोई सरकार करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। सीएम ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही है। किसान के लिए लागत कम, आमदनी डबल होनी चाहिए। अब हम किसान से एमएसपी पर फसल खरीदेंगे। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में पानी के बंटवारे को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों को आपस में लड़वा दिया। किसानों के खून की नदियां बहती थीं और कांग्रेसी मजे करते थे। उनका काम ही है लोगों को आपस में बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए और कांग्रेस छोड़ गए। और ये कांग्रेसी हम सबके सिर पर बैठ गए। सीएम यादव ने कहा कि अब एमपी का बुंदेलखंड प्यासा नहीं रहेगा।

मंदिरों का हवाला देकर सरकार पर बरसे जमीयत के सदर

● बोले-वे वक्फ की हिफाजत क्या करेंगे, जो अपनी धार्मिक संस्थाएं नहीं संभाल पा रहे



भोपाल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के सदर मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन जो लोग अपनी धार्मिक संस्थाओं के मामलों को ही ठीक से नहीं संभाल पा रहे, वे वक्फ की धार्मिक संपत्तियों और संस्थाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी मजहबी चीजों को ही नहीं बचा पा रहे हैं। अभी उनके मजहबी मामले, मंदिरों से जुड़े विवाद देख रहे हैं। जब वे अपनी चीजों को नहीं संभाल पा रहे, तो हमारी मजहबी चीजों की हिफाजत कैसे करेंगे। इसलिए हमारी हुकूमत से अदब के साथ दरखास्त है।

इतिहास में पहली बार ऐसा फैसला

मुफ्ती मोहम्मद ने कहा कि देश के इतिहास में अब तक हर धर्म की धार्मिक संस्थाओं और उससे जुड़ी संपत्तियों का संचालन उसी समुदाय के लोग करते आए हैं। हिंदू संस्थाओं में हिंदू, सिख संस्थाओं में सिख और ईसाई संस्थाओं में ईसाई प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन पहली बार मुस्लिम समाज के धार्मिक और सामुदायिक मामलों से जुड़े वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है। उन्होंने इसे मुस्लिम समाज के लिए चिंता और पीड़ा का विषय बताया। मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने कहा कि इस फैसले से यह आशंका पैदा होती है कि सरकार की नजर वक्फ की जमीनों, कब्रिस्तानों और अन्य संपत्तियों पर है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां वक्फ की हैं।

एमपी में सरकारी बसों के संचालन के 40 रूट तय

इलेक्ट्रॉनिक टिकट मिलेंगे, ट्रेकिंग डिवाइस हर दस सेकेंड में पता चलेगी लाइव लोकेशन

भोपाल। मध्य सरकार ने सरकारी बसों का संचालन करने के लिए 40 लंबे बस रूट तय कर दिए हैं। राज्य सड़क परिवहन स्कीम को लेकर राज्य सरकार ने बस रूटों और सरकार द्वारा दी जाने वाली बस सेवा सुविधा को लेकर तीस दिन में आपत्तियां और सुझाव बुलाए हैं। इसके बाद इन बसों के संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खास बात यह होगी कि बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मिलेंगे, जिन रूट्स पर ट्रेफिक ज्यादा है वहां अधिक से अधिक बसें दौड़ाकर यात्रियों को सेवा दी जाएगी और बसों में ऐसे ट्रेकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे जो हर दस सेकेंड में बस की लोकेशन यात्रियों को वेबसाइट पर बताएंगे। परिवहन विभाग द्वारा इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है कि मध्य प्रदेश यात्री बस परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा नोटिफाइ किए गए रूट्स पर बसों का संचालन किया जाएगा।



आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू आज नंदीयाल जिले के बानागनपल्ले गांव का करेंगे दौरा



नंदीयाल जिले में भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

एन. चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के बानागनपल्ले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य सरकार की "मी भूमि-मी हक्कू" पहल के तहत किसानों और भू-स्वामियों को पट्टादार पासबुक वितरित करेंगे तथा किसानों से संवाद भी करेंगे। राज्य सरकार के अनुसार, भूमि पुनर्सर्वेक्षण और अभिलेखों के आधुनिकीकरण के तहत हजारों गांवों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 29 लाख पट्टादार पासबुक वितरित की जा चुकी हैं।

अचानक 34 ब्रिगेडियरों को मेजर जनरल बनाने के पीछे क्या है पाकिस्तान की रणनीति?

पाकिस्तान की सेना ने एक साथ 34 ब्रिगेडियरों को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत कर बड़ा प्रशासनिक और रणनीतिक फेरबदल किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। एक ओर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान सीमा पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के हमलों में भी तेजी आई है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर पदोन्नति का उद्देश्य सेना के शीर्ष नेतृत्व को मजबूत करना, विभिन्न

सैन्य कमानों में नई नियुक्तियां करना और सुरक्षा हालात से निपटने के लिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाना है। मेजर जनरल स्तर के अधिकारी डिवीजन, महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्रों और रणनीतिक अभियानों का नेतृत्व करते हैं, इसलिए यह बदलाव सेना की परिचालन क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

पाकिस्तान के सामने इस समय आंतरिक आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता जैसी कई चुनौतियां हैं। ऐसे में सेना अपने नेतृत्व ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित कर संभावित सुरक्षा संकटों से निपटने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञ यह भी

मानते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति भविष्य में उच्च सैन्य नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया का भी हिस्सा होती है।

हालांकि, पाकिस्तान की सेना ने इस फैसले को नियमित पदोन्नति प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे केवल सामान्य प्रशासनिक कदम नहीं माना जा रहा। विश्लेषकों के अनुसार यह बदलाव संकेत देता है कि पाकिस्तान की सेना आने वाले समय में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने नेतृत्व को अधिक सक्रिय और सशक्त बनाना चाहती है।

महिलाओं और बच्चों की डिजिटल और साइबर सुरक्षा के लिए एनजीओ, महिला आयोग और गूगल एक मंच पर

राजेश धाकड़

इंदौर, डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा आज देश के सामने सबसे बड़ी सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों में शामिल हो गई है। इसी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, आहान फाउंडेशन और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के सहयोग से भोपाल में आयोजित विशेष एनजीओ मीट में डिजिटल सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग पर व्यापक विमर्श हुआ। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की सदस्य श्रीमती साधना स्थापक ने कहा कि डिजिटल युग ने जितने अवसर उपलब्ध कराए हैं, उतनी ही नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा केवल कानून या तकनीक का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की बदलती प्रकृति को देखते हुए डिजिटल जागरूकता, समय पर शिकायत और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को जन-आंदोलन का स्वरूप देना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग



सिखाना समय की आवश्यकता है। परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और शासन के समन्वित प्रयासों से ही ऐसा डिजिटल वातावरण बनाया जा सकता है, जहां प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें।

कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव श्री सुरेश तोमर भी उपस्थित रहे। 'रिस्पॉन्सिबल नेटिजन' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित संवाद में महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लेकर जमीनी अनुभव साझा किए तथा डिजिटल सुरक्षा को लेकर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में गूगल की डायरेक्टर (सर्च एंड जेनरेटिव एआई ट्रस्ट एंड सेफ्टी) सुश्री स्निग्धा भारद्वाज ने 'चाइल्ड सेफ्टी एंड एआई' विषय पर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास बच्चों और समाज के हितों को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन

जोखिमों की पहचान और बच्चों के लिए जिम्मेदार डिजिटल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं गूगल के ट्रस्ट एंड सेफ्टी विभाग के श्री समीर ने साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और सुरक्षा मानकों की जानकारी साझा की। आहान फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री सोनाली पाटणकर ने डिजिटल सुरक्षा पर आयोजित विशेष सत्र में साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न, फर्जी लिंक, डेटा सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग से जुड़े व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता आज केवल एक कौशल नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है।

कार्यक्रम के समापन पर सभी सहभागी स्वयंसेवी संस्थाओं ने महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, समावेशी और विश्वासपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि शासन, तकनीकी संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है तथा डिजिटल भारत के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सकती है।

राष्ट्रीय संत स्वामी श्री अरुणानंद जी महाराज ने घनश्याम पिरोनिया को डायरी व पेन भेंट कर दिया आशीर्वाद



खुशबू श्रीवास्तव

समाज और देशहित में कलम का सदुपयोग करने का दिया संदेश, साफा पहनाकर किया सम्मान

इंदौर। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान भाजपा प्रवक्ता घनश्याम जी पिरोनिया ने पूर्व राज्य मंत्री दिलीप राजपाल जी के निवास पर आयोजित एक आध्यात्मिक एवं सम्मान समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत एक तू ही जयगुरुदेव सद्गुरु स्वामी श्री अरुणानंद जी महाराज साहेब ने घनश्याम पिरोनिया को डायरी एवं पेन भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया। स्वामी श्री अरुणानंद जी महाराज ने आशीर्वाचन देते हुए कहा कि कलम और कागज का सदैव समाज, राष्ट्र

और मानवता की भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए। उन्होंने जनसेवा, सद्भाव और नैतिक मूल्यों के साथ कार्य करते रहने का संदेश दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने साफा पहनाकर संत श्री एवं अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर पवन यादव, शफीक बाबा वारसी (प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सर्व धर्म सूफी संत महासंघ), मां साध्वी श्री अनंता देवी (सचिव, एक तू ही जयगुरुदेव), सूफी अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष जैन, एडवोकेट महेंद्र हलधर, पी.एल. मधुराज, ओमप्रकाश वर्मा, जानकीलाल पटेरिया (इंटक नेता), किशन भालसे, नियमत खान (स्वतंत्रता सेनानी) एवं परिहार सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

विशेष राजस्व वसूली शिविर 10 जुलाई को, संपत्तिकर की अग्रिम राशि जमा करने पर मिलेगी 5 प्रतिशत की छूट

नवल किशोर

संपत्तिकर वसूली में तेजी लाने के लिए निगम प्रशासन की विशेष पहल, अधिकारियों को दिए गए निर्देश

कटनी। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्तिकर की वसूली को गति देने एवं अधिक से अधिक करदाताओं को अग्रिम कर जमा करने के लिए शुक्रवार 10 जुलाई को विशेष राजस्व वसूली शिविर आयोजित किया जाएगा।

यह शिविर संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें शासन के प्रावधान अनुसार अग्रिम संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देश पर राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक द्वारा आदेश जारी कर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व उपनिरीक्षक एवं वार्ड वसूली कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने वार्डों



में अधिकाधिक संपत्ति करदाताओं से संपर्क कर उन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक संपत्तिकर का अग्रिम भुगतान करने के लिए प्रेरित करें।

राजस्व अधिकारी श्री पाठक ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि संपत्ति कर वसूली अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिकतम कर संग्रह सुनिश्चित किया जाए। निगम प्रशासन ने अधिक से अधिक नागरिकों से शासन द्वारा प्रदाय की जा रही छूट का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री के आगामी दौरे की तैयारियों को लेकर कलेक्टर व एसपी ने किया स्थल निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

दिलीप पाटीदार

धार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगामी धार जिले में प्रस्तावित कार्यक्रम और 'राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन' की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय हो गया है। आज कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपेड का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजेन्द्रसुरी महाविद्यालय परिसर में होगा आयोजन यह राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन सरदारपुर के राजगढ़ स्थित राजेन्द्रसुरी महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री मीना ने आज महाविद्यालय परिसर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल, हेलीपेड, मंच



निर्माण, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की।

अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के साथ पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री के

आगमन और सहकारिता सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समय-सीमा के भीतर और उच्च मानकों के अनुरूप पूरी कर ली जाएं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और आमजन की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा ने कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने इस गरिमामयी कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है।

बस का टायर फटने के बाद घर्षण बढ़ गया, जिससे अत्यधिक गर्मी पैदा हुई और आग लग गई। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। तकनीकी विशेषज्ञ भी बस का निरीक्षण करेंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा केवल टायर फटने के कारण हुआ या फिर किसी अन्य यांत्रिक खराबी ने भी इसमें भूमिका निभाई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पुलिस और ट्रेवल्ल्स प्रबंधन ने मिलकर यात्रियों के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित इंदौर रवाना कर दिया गया।

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों भूमि पूजन

नवल किशोर

कटनी। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा शहर के समग्र विकास के क्रम में बुधवार 8 जुलाई को लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 3 में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन समारोह महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरि, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती सरला संतोष मिश्रा MIC प्रभारी सदस्य डॉक्टर रमेश सोनी सुभाष साहू सुरेन्द्र गुप्ता की गरिमामयी मौजूदगी में आयोजित किया गया। भूमिपूजन वार्ड की वरिष्ठ महिला श्रीमती शकुन बर्मन के कर कमलों से विधिवत संपन्न कराया वार्ड वासियों को विकास कार्यों की नई सौगात दी गई।

आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम

इस अवसर पर नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वार्ड में लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इनमें 32.57 लाख रुपये की लागत से शासकीय स्कूल पहरा एवं सुभाष तिवारी के मकान से शंकर दुबे के मकान तक आरसीसी नाली निर्माण, 14.68 लाख रुपये की लागत से नंदन कानन गार्डन के बाजू से आरसीसी सड़क निर्माण, 5 लाख 87 हजार रुपये की लागत से गहोई कॉलोनी में नीरज रजक के घर से सीसी नाली निर्माण कार्य तथा लगभग 60 लाख रुपये की लागत से 3 नवीन ट्रांसफार्मर एवं 74 विद्युत पोल स्थापित किए जाने का कार्य शामिल है। यह विद्युत कार्य पन्नी कॉलोनी, कुठला,



पहरा क्षेत्र सहित वार्ड के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही वार्ड की विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 60 लाख रुपये की लागत से 3 नवीन ट्रांसफार्मर एवं 74 विद्युत पोल स्थापित किए जाएंगे। यह कार्य पन्नी कॉलोनी, कुठला, पहरा क्षेत्र सहित वार्ड के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

हर वार्ड तक बेहतर मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प- महापौर श्रीमती सूरि

इस अवसर पर महापौर श्रीमती सूरि ने कहा कि नगर निगम शहर के प्रत्येक वार्ड में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। सड़क, नाली एवं विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा की

विद्युत पोल ट्रांसफार्मर लगाने से अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा लाभ। क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती मिश्रा ने कहा कि वार्ड क्रमांक 3 के नागरिक लंबे समय से इन विकास कार्यों की अपेक्षा कर रहे थे। आज इन कार्यों के भूमिपूजन के साथ वार्ड के विकास को नई गति मिलेगी। सड़क, नाली, विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित होने से हजारों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

इनकी रही मौजूदगी

कार्यक्रम के दौरान एमआईसी सदस्य सर्व श्री डॉ. रमेश सोनी, सुभाष साहू, सुरेन्द्र गुप्ता, उपयंत्री मोना करिरा, ठेकेदार अरुण चक्रवर्ती, रजनीश तिवारी समाजसेवी संजय मिश्रा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रवासियों ने वार्ड में कराए जा रहे विकास कार्यों के लिए महापौर श्रीमती सूरि, क्षेत्रीय पार्षद तथा नगर पालिक निगम प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त किया। नागरिकों ने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से वार्ड की वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा तथा क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का सहज मार्ग है सहजयोग

गृहस्थ धर्म का विवेकपूर्ण पालन ही सहजयोग का वास्तविक स्वरूप है। योग का वास्तविक अर्थ है जुड़ना, मिलना या एकत्व की अवस्था को प्राप्त करना। यद्यपि समय के साथ अनेक प्रकार की योग पद्धतियाँ प्रचलित हुईं, किन्तु प्रत्येक योग का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना तथा आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति का प्रत्येक अणु और परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी पंचमहाभूतों से निर्मित होने के कारण पूर्णता की खोज में रहता है। उसकी यह खोज तभी पूर्ण होती है जब वह अपने भीतर स्थित आत्मतत्त्व का अनुभव करता है और परम चेतना से उसका योग स्थापित होता है। आत्मज्ञान, आत्मविस्तार और आत्मसाक्षात्कार तक पहुँचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, किन्तु सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही है—असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा सीमित चेतना से असीम चेतना की ओर अग्रसर होना। अनेक आध्यात्मिक मार्ग सांसारिक जीवन से विरक्ति की प्रेरणा देते हैं, जबकि सहजयोग यह सिखाता है कि गृहस्थ जीवन का त्याग किए बिना भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम को जीवन का आधार माना गया है और गृहस्थ धर्म का विवेकपूर्ण, संतुलित तथा मर्यादित पालन ही सहजयोग का वास्तविक स्वरूप है। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा प्रदत्त सहजयोग आत्मसाक्षात्कार की ऐसी सहज, सरल और सर्वसुलभ पद्धति है, जिसमें साधना का आरंभ वहीं से होता है जहाँ तक पहुँचने के लिए अन्य साधकों को वर्षों के कठिन तप या अनेक जन्मों की साधना करनी पड़ सकती है। श्री माताजी की कृपा से आत्मसाक्षात्कार के माध्यम से



साधक क्षणभर में परम चैतन्य से जुड़ने का अनुभव कर सकता है। इस मार्ग में न तो गृहस्थ जीवन का त्याग आवश्यक है, न किसी संबंध या भौतिक वस्तु का परित्याग और न ही किसी प्रकार का आर्थिक शुल्क। आवश्यक है केवल निर्मल हृदय, पूर्ण समर्पण और नियमित साधना। आत्मसाक्षात्कार के बाद प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल कुछ मिनट निर्विचार ध्यान में स्थित रहकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ बनाए रखना सहजयोग का महत्वपूर्ण अंग है। सहजयोग हमें अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या तथा दुर्व्यसनों का त्याग करना सिखाता है, जबकि प्रेम, करुणा, संतोष, क्षमा और आनंद जैसे सद्गुणों को जीवन में स्थापित करता है। यही कारण है कि सहजयोगी वही बन सकता है जो अपने पारिवारिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए प्रेमपूर्ण, संतुलित, आनंदमय और संतुष्ट जीवन व्यतीत करे। सहजयोग पूर्णतया निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2700 800 पर संपर्क करें अथवा sahajayoga.org.in वेबसाइट पर अपने निकटतम सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी प्राप्त करें।

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जितेंद्र का अखबार वितरक संघ ने किया सम्मान



कोरबा। छत्तीसगढ़ अखबार वितरक संघ, ने जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष बनाए गए जितेंद्र सोनी को उनके कार्यालय पहुंचकर पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि सोनी अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए

संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। जितेंद्र सोनी ने संघ के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष विपेंद्र कुमार साहू, जिला सचिव जय सिंह नेताम, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी राठौर, मीडिया प्रभारी रामायण सिंह, सह सचिव राय सिंह तथा कृष्णा निर्मलकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सीसीटीवी की मदद से ऑटो में छूटा लैपटॉप खोजकर कटनी पुलिस ने वास्तविक मालिक को सुरक्षित सौंपा

कटनी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से कटनी पुलिस ने ऑटो में छूटे एक लैपटॉप को खोजकर उसके वास्तविक मालिक को सुरक्षित वापस सौंप दिया। इस त्वरित कार्रवाई से फरियादी ने पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन में संचालित सीसीटीवी मॉनिटरिंग के तहत यह सफलता मिली। फरियादी घनेन्द्र कुमार त्रिपाठी और उनकी पुत्री शालिनी तिवारी ने पुलिस को बताया कि वे दुर्गा चौक से थाना तिराहा जाने के लिए ऑटो में सवार हुए थे, जहां यात्रा के दौरान उनका लैपटॉप ऑटो में ही छूट गया। सूचना मिलते ही सीसीटीवी टीम



ने बताए गए मार्ग के कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में खिरहनी ब्रिज और थाना तिराहा के कैमरों में संबंधित ऑटो

दिखाई दिया, जिसके आधार पर वाहन का पंजीयन क्रमांक एमपी-21 जेडबी-7850 चिन्हित किया गया।

आरटीओ रिकॉर्ड से चालक की जानकारी प्राप्त कर उससे संपर्क किया गया। चालक ने बताया कि लैपटॉप उसके पास सुरक्षित रखा हुआ है। इसके बाद थाना एनकेजे पुलिस और सीसीटीवी टीम ने लैपटॉप प्राप्त कर फरियादी को विधिवत सुपुर्द कर दिया। लैपटॉप सुरक्षित वापस मिलने पर फरियादी और उनके परिजनों ने कटनी पुलिस की संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई की सराहना की। इस कार्य में दीक्षा रेडियो की अनामिका सोनकर, मृदुल त्रिपाठी, देवराज सिंह, पुष्पेंद्र यादव तथा थाना एनकेजे पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जन चौपाल में गूंजी जनता की समस्याएं, विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

चीफ हेमंत भार्गव

जल निगम के ठेकेदारों पर भड़के विधायक, कहा- टूटी सीसी सड़कें जल्द ठीक करें, नहीं तो करें ब्लैकलिस्ट राजस्व, बिजली और जल निगम की शिकायतों की भरमार, सीमांकन के सबसे ज्यादा आवेदन पहुंचे हर महीने शनिवार को लगेगी जन चौपाल, जनता की समस्याओं का मौके पर होगा समाधान सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं की नजर बर्दाश्त नहीं, खेल मैदान और मुक्तिधाम के लिए भूमि आरक्षित करने के निर्देश

करैरा: करैरा में आयोजित जन चौपाल में विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जन चौपाल में बिजली, पानी, सड़क, राजस्व, स्वास्थ्य, पेंशन, आवास तथा अन्य जनहित से जुड़े मामलों पर बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रहीं। इनमें सीमांकन, भूमि विवाद, नामांतरण और शासकीय भूमि से जुड़े मामलों के आवेदन प्रमुख रहे। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से लंबित राजस्व मामलों का समय पर समाधान नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया



जाए। जन चौपाल में बिजली आपूर्ति और जल निगम से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में सामने आईं। ग्रामीणों और नगरवासियों ने बताया कि जल निगम के ठेकेदार पाइपलाइन डालने के बाद सीसी सड़कों को खोदकर छोड़ देते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनकी मरम्मत नहीं कराते। इसके कारण सड़कें उबड़-खाबड़ हो गई हैं और आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि यह समस्या किसी एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के अनेक गांवों की है।

इस पर विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने जल निगम के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सभी ठेकेदारों को तत्काल अधूरे

कार्य पूरे करने के निर्देश दिए जाएं। जिन ठेकेदारों द्वारा समय पर कार्य नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जन चौपाल के दौरान विधायक ने कहा कि जन चौपाल केवल शिकायतें सुनने का मंच नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास एवं समाधान का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और लोगों की समस्याओं का यथासंभव उसी दिन समाधान करने का प्रयास किया जाए। विधायक ने यह भी कहा कि अब प्रत्येक माह के

एक शनिवार को नियमित रूप से जन चौपाल आयोजित की जाएगी, ताकि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने यह भी नाराजगी जताई कि जन चौपाल की पर्याप्त जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, जिसके कारण आम नागरिकों की अपेक्षा अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या अधिक दिखाई दी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि भविष्य में जन चौपाल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बैठक के दौरान विधायक ने सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं की नजर को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाए। उन्होंने सिरसौद में लगभग साढ़े सात बीघा शासकीय भूमि को खेल मैदान के लिए आरक्षित करने तथा करैरा मंडी के पीछे खेल मैदान एवं मुक्तिधाम के लिए भूमि आरक्षित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जन चौपाल में एसडीएम शिवदयाल धाकड़, तहसीलदार ललित शर्मा, रेंजर लक्ष्मण सिंह मीणा, थाना प्रभारी विनोद छाबई, बीएमओ डॉ. नारायण सिंह कुशवाहा, डॉ. अजय गुर्जर, पीएचई विभाग से हिमांशी गुप्ता, विद्युत विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी अधिकारियों द्वारा दिया गया। !!

विद्यार्थियों को आधुनिक एवं सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाओं हेतु कराए जा रहे उन्नयन कार्यों की गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान - निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार

किशोर कुशवाहा

के सी एस विद्यालय एवं निर्माणाधीन ई-लाइब्रेरी का किया निरीक्षण, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश ई-लाइब्रेरी का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर विद्यार्थियों के लिए करें प्रारंभ

कटनी विद्यार्थियों को आधुनिक, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम कटनी द्वारा विद्यालयों में कराए जा रहे उन्नयन कार्यों का बुधवार को निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने के सी एस विद्यालय एवं निर्माणाधीन ई-लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण एवं मरम्मत कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को शीघ्र बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान सहायक यंत्री अनिल



जायसवाल, नोडल अधिकारी आदेश जैन, उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी, शाला प्राचार्य रूप भास्कर, शिक्षक रिजवान हसन खान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कटनी द्वारा के सी एस विद्यालय, विद्यालय परिसर स्थित ई-लाइब्रेरी सहित निगम के अन्य विद्यालयों में भी आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन कार्य प्राथमिकता के साथ कराए जा

रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन एवं अनुकूल अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

दिनारा में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का आरोप, बिना अनुमति पेड़ों की कटाई से मचा हड़कंप

एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी आंखे खोलो भू माफियाओं से बचाओ शहर

करैरा अनुविभाग के दिनारा क्षेत्र में धांधू पुल के समीप भू-माफियाओं द्वारा नियमों को दरकिनार कर कृषि भूमि पर कथित रूप से अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगभग तीन बीघा रकबे में बिना भूमि डायवर्सन और आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियों के प्लॉटिंग का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के लिए जेसीबी और अन्य मशीनों का उपयोग करते हुए खेत की मूल संरचना बदल दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस दौरान दो दर्जन से अधिक हरे-भरे पेड़ों को भी बिना सक्षम अनुमति के काट दिया गया, जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंची है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि करैरा अनुविभाग में भूमि संबंधी अनियमितताओं पर कार्रवाई का दायरा सीमित दिखाई देता है, जहां किसी एक मामले में औपचारिक कार्रवाई कर शेष मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के हौसले लगातार बुलंद

हो रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करना है तो नियमानुसार डायवर्सन, नगर एवं राजस्व विभाग की अनुमति तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है, लेकिन यहां इन प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर भूमि अभिलेख, स्वीकृतियां, पेड़ों की कटाई की अनुमति तथा कॉलोनी निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच



कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध बसाहट का सिलसिला और तेज हो सकता है।



आठ दिन की बारिश भी नहीं झेल पाया एक माह किया डामरीकरण, पैचवर्क पर करोड़ों फूंकने के बाद फिर उखड़ी सड़कें, अब ठेकेदारों पर जिम्मेदारी डाल रहा निगम

इंदौर। नगर निगम ने एक माह पूर्व बारिश को लेकर कहा था कि शहर में पैचवर्क और डामरीकरण करवाया जा रहा है ताकि बारिश में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन यह क्या शहर की सड़कों पर किया गया निगम का बहुप्रचारित पैचवर्क आठ दिन की बारिश भी नहीं झेल पाया और बह गया। जिन सड़कों को लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर 'दुरुस्त' बताया गया था, वे फिर से गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। नगर निगम ने पिछले दिनों चार एजेंसियों को खस्ताहाल सड़कों के डामरीकरण और पैचवर्क का ठेका दिया था। शर्तें भी रखी गईं, दावे भी किए गए, लेकिन पहली ही बारिश ने उन दावों की पोल खोल दी। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर डामर की परतें उखड़ चुकी हैं और सड़कें फिर दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। सवाल यह है कि जब काम हुआ था तब गुणवत्ता की जांच किसने की थी और अब जनता की जान जोखिम में डालने के बाद जिम्मेदारी तय करने की याद क्यों आ रही है? अब निगम अधिकारियों ने भवन अधिकारियों और वरिष्ठ इंजीनियरों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जांच होगी कि सड़कें आखिर उखड़ी क्यों? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर काम मानकों के अनुसार हुआ था तो सड़कें इतनी जल्दी खराब कैसे हो गईं? और यदि काम घटिया था तो भुगतान किस आधार पर किया गया? निगम का कहना है कि यदि गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित ठेकेदारों से उनके खर्च पर मरम्मत कराई जाएगी। जब तक घटिया निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक सड़कों पर गड्ढे और निगम के दावे दोनों साथ-साथ चलते रहेंगे।

फायर सेफ्टी पर फिर चला प्रशासन का डंडा : निगम की फायर टीम ने गुरुवार को भी 152 संस्थानों पर कार्रवाई की

इंदौर। शहर में अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन का अभियान एक बार फिर तेज हो गया है। फायर सेफ्टी इंतजामों के बिना धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग सेंटरों और संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए कई जगहों को सील किया गया। अब तक 152 से ज्यादा संस्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये संस्थान इतने लंबे समय तक बिना सुरक्षा मानकों के कैसे संचालित होते रहे? भंवरकुआं, विजय नगर सहित कई इलाकों में बुधवार को हुई जांच में कई संस्थानों में आग से बचाव के बुनियादी इंतजाम तक नहीं मिले। कहीं फायर



फाइटिंग सिस्टम नदारद था तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ कागजों में मौजूद निकला। कार्रवाई के बाद कुछ संस्थानों को सुधार का मौका दिया गया, जबकि कई को सीधे सील कर दिया गया। प्रशासन विभाग

का दावा है कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि जब ये संस्थान महीनों और वर्षों से संचालित हो रहे थे तब जिम्मेदार विभागों की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या हादसे का

इंतजार किया जा रहा था? कलेक्टर शिवम वर्मा और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर चल रहे अभियान में सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन कार्रवाई के साथ जवाबदेही भी तय होना जरूरी है। सिर्फ संस्थानों को सील करने की तस्वीरें जारी करने से काम नहीं चलेगा, यह भी बताना होगा कि नियमों की अनदेखी करने वालों को संरक्षण किसने दिया। फिलहाल प्रशासन की मुहिम जारी है, लेकिन शहर यह जानना चाहता है कि यह अभियान स्थायी सुधार लाएगा या कुछ दिनों की सख्ती के बाद फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा।

ट्रैफिक जाम में फंसे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों को लगाई फटकार



इंदौर। शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम की समस्या अब आम लोगों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी प्रभावित करने लगी है। बुधवार शाम नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफिला भी एमआर-10 ब्रिज पर भारी ट्रैफिक जाम में फंस गया। वीआईपी मूवमेंट के बावजूद उनका काफिला काफी देर तक वाहनों की लंबी कतार में रेंगता रहा। यह घटना शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था की ओर इशारा करती है। शाम के समय कार्यालयों और बाजारों से लौटने वाले लोगों के कारण रिंग रोड, बायपास, एमआर-10 और अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है, जिससे लंबा जाम लग जाता है। निर्माण कार्य और बारिश बने बड़ी वजह- शहर में विभिन्न स्थानों पर चल रहे फ्लाईओवर, सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण कार्यों के कारण कई मार्ग संकरे हो गए हैं। बारिश के चलते गड्ढों और जलभराव

की समस्या ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। कई स्थानों पर लगाए गए बैरिकेड्स के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे पीक आवर्स में लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। कलेक्टर ने किया निरीक्षण- लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों के साथ जाम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को अधूरे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और समय-सीमा में काम पूरा करने को कहा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों के कारण आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। शहरवासियों की उम्मीद है कि प्रशासन की सख्ती और निर्माण कार्यों में तेजी आने से आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। हालांकि, फिलहाल इंदौर के प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

डिजिटल लर्निंग में इंदौर अत्वल, विधानसभा-2 ने हासिल किया पहला स्थान

इंदौर। डिजिटल लर्निंग अभियान में इंदौर जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-2 ने सर्वाधिक सहभागिता और सक्रियता के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। अभियान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों को जोड़ने, प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरा कराने तथा ऑनलाइन गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों का सकारात्मक

परिणाम सामने आया है। जानकारी के अनुसार विधानसभा-2 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक लोगों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जिससे यह क्षेत्र जिले में शीर्ष पर पहुंच गया। वहीं राऊ, विधानसभा-1 और विधानसभा-3 ने भी संतोषजनक प्रदर्शन किया। इंदौर जिले में कुल नौ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। दूसरी ओर महू विधानसभा अभियान में सबसे पीछे रही। यहां अपेक्षित संख्या में

कार्यकर्ताओं और हितग्राहियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं जोड़ा जा सका। देवापुर और विधानसभा-4 की स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही, जहां निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि कम दर्ज की गई। अभियान से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि डिजिटल माध्यमों से सीखने और प्रशिक्षण प्राप्त करने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पिछड़े क्षेत्रों में विशेष

अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा, ताकि डिजिटल सशक्तिकरण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल लर्निंग आज के दौर में कौशल विकास और सूचना तक आसान पहुंच का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। इंदौर पहले भी विभिन्न डिजिटल और नवाचार आधारित पहलों में अग्रणी रहा है तथा यह उपलब्धि उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

90 डिग्री का खतरा हटाने में सालों लगा दिए! अब बदला अलाइनमेंट, तीन लेन ब्रिज का नया प्लान

इंदौर। जिस 90 डिग्री मोड़ को इंजीनियरिंग की बड़ी खामी माना जा रहा था, उसी डिजाइन पर वर्षों तक फाइलें घूमती रहीं और शहर ट्रैफिक की परेशानी झेलता रहा। अब जाकर प्राथिकरण ने एमआर-12 के अलाइनमेंट में बदलाव को मंजूरी दी है। दावा है कि इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और यातायात को नई रफ्तार मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मोड़ इतना

खतरनाक था तो उसे योजना में शामिल ही क्यों किया गया? कान्ह नदी पर नए ब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज के लिए डिजाइन में संशोधन किया गया है। पहले प्रस्तावित 90 डिग्री मोड़ को खत्म कर नया सीधा अलाइनमेंट मंजूर किया गया है। इसके साथ ही रेलवे ओवरब्रिज को तीन लेन का बनाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे भविष्य में ट्रैफिक जाम



और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। दूसरी ओर शहर की महत्वपूर्ण परियोजनाएं अब भी धीमी रफ्तार का शिकार हैं। मूसाखेड़ी ब्रिज का काम अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद धार्मिक स्थलों के कारण अटका हुआ है। हर बार नई बाधाएं सामने आने से परियोजना की समय-सीमा लगातार बढ़ रही है और जनता इंतजार करने को मजबूर है। कलेक्टर ने एमआर-10,

खजराना ब्रिज और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इंदौर में पुल और सड़क परियोजनाएं अक्सर संशोधन, विवाद और देरी की भेंट चढ़ती रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बदला हुआ अलाइनमेंट और नई डिजाइन कागजों से निकलकर कब धरातल पर दिखाई देती है।

सांसद बंटी विवेक साहू आंधी-तूफान, तेज बारिश और तमाम कठिनाईयों के बीच भी 9 दिनों से लगातार कर रहे 14 दिवसीय धार्मिक पदयात्रा

नवल किशोर

सांसद छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर की 274 किमी की धार्मिक पदयात्रा पूरी कर कटनी जिले में पहुंचे सिहोरा के विधायक सहित भाजपा के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और आमजनों ने किया सांसद का अभिनंदन और भव्य स्वागत सांसद अपने दृढ़ संकल्प के साथ मैहर तक 14 दिन में पूरी करेंगे 375 किमी की धार्मिक पदयात्रा कटनी होते हुए मैहर पहुंचेगी सांसद की 14 दिवसीय धार्मिक पदयात्रा

कटनी। सांसद बंटी विवेक साहू अपने दृढ़ संकल्प के साथ पिछले 9 दिनों से आधी तूफान, तेज बारिश और तमाम कठिनाईयों के बीच भी लगातार धार्मिक पदयात्रा कर रहे हैं। इस बीच सांसद ने छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर की 274 किमी की धार्मिक पदयात्रा पूरी करते हुए कटनी जिले में प्रवेश कर लिया है। सांसद बंटी विवेक साहू ने 1 जुलाई को छिंदवाड़ा से अपनी धार्मिक पदयात्रा की शुरुआत की थी, वे 14 दिन में 14 जुलाई को मैहर तक 375 किमी की धार्मिक पदयात्रा पूरी करेंगे। सांसद अपने सैकड़ों पदयात्रियों के साथ में 14 जुलाई को मैहर में मां शारदा में दरबार में माथा टेककर मां शारदा से मध्यप्रदेश सहित छिंदवाड़ा और पांडुर्णा के आमजनों की सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली की कामना के साथ अच्छी बारिश की प्रार्थना भी करेंगे।

पूरे प्रदेश में आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाएगी सांसद



की धार्मिक पदयात्रा-उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगुभाई पटेल ने सांसद बंटी विवेक साहू को भेजे गए पत्र में लिखा था कि सांसद बंटी विवेक साहू के द्वारा जनकल्याण और देश की समृद्धि के लिए छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, कटनी व मैहर तक की पदयात्रा किए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मां शारदा 51 शक्तिपीठों में से एक है, वे विद्याकला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, उनके चरणों में समर्पित आराधना सराहनीय पहल है। सांसद बंटी विवेक साहू की धार्मिक पदयात्रा मंगलकारी सिद्ध होगी।

सांसद ने कटनी जिले में किया प्रवेश, सिहोरा के जनप्रतिनिधियों ने किया भव्य स्वागत-मध्यप्रदेश

सहित छिंदवाड़ा और पांडुर्णा के आमजनों की सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली की कामना के साथ अच्छी बारिश की प्रार्थना को लेकर अपनी 14 दिवसीय 375 किमी की छिंदवाड़ा से मैहर तक की धार्मिक पदयात्रा पर निकले सांसद बंटी विवेक साहू छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर जिले की 274 किमी धार्मिक पदयात्रा पूरी करते हुए 9 जुलाई को देर शाम कटनी जिले के छपरा में प्रवेश कर लिया है। गुरुवार को सिहोरा विधायक संतोष वरकड़े, सिहोरा जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमति रश्मि मनेन्द्र अग्निहोत्री, सिहोरा जनपद पंचायत सदस्य नीरज पांडे, अखिल भारतीय असादी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय असादी, साहू समाज के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में भाजपा

के अन्य पदाधिकारियों सहित छिंदवाड़ा से पहुंचे भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं आमजनों ने सांसद बंटी विवेक साहू का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया और इस धार्मिक पदयात्रा में शामिल भी हुए।

अब कटनी होते हुए मैहर पहुंचेगी सांसद की धार्मिक पदयात्रा-विदित हो कि सांसद बंटी विवेक साहू की 14 दिवसीय 375 किमी की धार्मिक पदयात्रा छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर के बाद अब कटनी होते हुए मैहर पहुंचेगी। कटनी में 10 जुलाई को द्वाद धाम में रात्रि विश्राम होगा तदोपरांत 11 जुलाई को प्रातः यात्रा प्रारम्भ होगी। इस दौरान सांसद अपने सैकड़ों पदयात्रियों के साथ में अंतिम 4 दिनों में 110 किमी की धार्मिक पदयात्रा करेंगे। सांसद बंटी विवेक साहू 14 जुलाई को मैहर पहुंचकर मां शारदा के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश सहित छिंदवाड़ा और पांडुर्णा के आमजनों की सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली की कामना के साथ अच्छी बारिश की प्रार्थना भी करेंगे।

14 दिवसीय धार्मिक पदयात्रा के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू प्रतिदिन सुबह और देर शाम को पदयात्रा की सफलता की कामना के साथ में मां शारदा की पूजा अर्चना व आरती के साथ धार्मिक पदयात्रा की शुरुआत और संपन्न करते हैं। इस दौरान वे पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पदयात्रा के मार्ग में 10 हजार पंचतत्व सीड बॉल और विभिन्न स्थानों वनविभाग एवं आमजनों के सहयोग से पौधे रोपित भी कर रहे हैं।

सहकारिता एवं पंजीयक आयुक्त श्री दीपक सिंह ने इंदौर संभाग के सहकारिता विभाग की समीक्षा की

ऋण वसूली, सदस्यता अभियान और केसीसी वितरण में लक्ष्य आधारित कार्य करने के लिए निर्देश

राजेश धाकड़



लंबित अंकेक्षण, अंकेक्षण शुल्क वसूली, किसानों को ऋण वितरण एवं वसूली, पैक्स के बहुउद्देशीय व्यवसाय, पैक्स कम्प्यूटरीकरण, दुग्ध सहकारी संस्थाओं के गठन एवं पंजीयन, रासायनिक उर्वरकों के वितरण तथा सहकारी संस्थाओं के खाते सहकारी बैंकों में संचालित किए जाने सहित विभिन्न विषयों की संस्थावार एवं अधिकारीवार समीक्षा की गई।

श्री दीपक सिंह ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को नियमित ऋणों की 100 प्रतिशत तथा बकाया ऋणों की 50 प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के लिए माहवार लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रिस योजना के तहत एनपीए ऋणों की वसूली के लिए जिला कलेक्टरों की एजेंडा सूची में लक्ष्य निर्धारण कराने के भी

निर्देश दिए। बैठक में संभागीय संयुक्त आयुक्त को पैक्स सदस्यता अभियान एवं नए केसीसी वितरण की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ऋण वसूली में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं करने तथा कालातीत ऋणों के मामलों में संबंधित स्वीकृति अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए। आयुक्त ने अकार्यशील सहकारी संस्थाओं के नियमानुसार पंजीयन निरस्त करने के लिए माहवार कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने को कहा। झाबुआ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को ऋण वसूली में विशेष प्रयास करते हुए बैंक को कमजोर श्रेणी से बाहर लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक में संभागीय संयुक्त आयुक्त श्री बी.एल. मकवाना ने पॉवरपॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न विषयों की प्रगति से अवगत कराया। इसके बाद जिलावार वन-टू-वन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अधिक मेहनत, लगन और लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए।

लघु वेतन कर्मचारीसंघ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को सौपा ज्ञापन



नवल किशोर

कटनी । मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा कटनी के जिलाध्यक्ष पूर्णेश उइके एवं मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज दिनांक 09 जुलाई को संघ के द्वारा श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी कटनी से मुलाकात कर उनका फूलमाला पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की समस्या से अवगत कराया गया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ई अटेंडेंस से छूट देने हेतु चर्चा कर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के नाम का ज्ञापन सौपा गया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने उचित समाधान हेतु सहयोग करने आश्वासन दिया है उक्त ज्ञापन में संघ के पदाधिकारी अजय गौतम उप प्रांताध्यक्ष प्रमोद मिश्रा सेवानिवृत्त शिक्षक मनोज श्रीवास सौरभ सिंह राकेश जसूजा अजीमुद्दीन शाह नीलेश पौराणिक कमलेश पांडेय भागीरथ तिवारी अध्यक्ष स्थाई कर्मि संघ धर्मेन्द्र राज बालकदास अरुण मिश्रा सतीश पटेल अभिषेक सिंह मरावी आयुष पांडेय वर्षा देशमुख सत्येंद्र कोरी रामलोचन यादव अन्य उपस्थित रहे।

शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी और एनीमिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए

यूनीसेफ के साथ मिलकर करेंगे कार्य: शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल से वल्लभ भवन में यूनीसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में यूनीसेफ इंडिया के उप प्रतिनिधि (कार्यक्रम) श्री जैस्पर मिलर, यूनीसेफ इंडिया की चीफ फील्ड सर्विसेज सुश्री सोलेदाद हेरेरो, यूनीसेफ मध्यप्रदेश के प्रमुख श्री विलियम हैनलोन और मध्यप्रदेश के कम्यूनिकेशन स्पेशलिस्ट श्री अनिल गुलाटी उपस्थित रहे। बैठक में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी, एनीमिया नियंत्रण, कुपोषण, बाल विवाह की रोकथाम तथा उच्च जोखिम गर्भावस्था के प्रभावी प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने तथा एनीमिया की चुनौती से निपटने के लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। राज्य सरकार जिला स्तर पर विशेषज्ञों की भर्ती कर मानव संसाधन की कमी दूर करने की दिशा में कार्य कर रही है। हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री



श्री शुक्ल ने कहा कि चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने इस कार्ययोजना के निर्माण में यूनीसेफ से तकनीकी सहयोग का आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यूनीसेफ राज्य के मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण में सहयोग कर सकता है, ताकि वे जिलों में प्रशिक्षण देकर उच्च जोखिम गर्भावस्था की समय पर पहचान, सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु देखभाल को मजबूत कर सकें। उन्होंने पंचायतों के सहयोग से राज्य स्तरीय

जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने यूनीसेफ से ऐसे सरल एवं प्रभावी मुख्य संदेश उपलब्ध कराने का आग्रह किया, जिन्हें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी और विभागीय समन्वय से एनीमिया, शिशु एवं मातृ मृत्यु तथा बाल विवाह जैसी चुनौतियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के मध्यप्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता की यूनीसेफ प्रतिनिधि श्री मिलर ने की सराहना: यूनीसेफ इंडिया के उप प्रतिनिधि (कार्यक्रम) श्री मिलर ने शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने इस दिशा में राज्य द्वारा लागू किए जा रहे 'सुमन रोडमैप' की प्रशंसा की। साथ ही, राज्य में मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनित्स (एमएनसीयू) की स्थापना की पहल के लिए भी मध्यप्रदेश को बधाई दी। सुश्री सोलेदाद हेरेरो ने कुपोषण और बाल विवाह के परस्पर संबंधों पर चर्चा की।

ग्वालियर-चंबल में आज हेवी रेन, भिंड में रेड अलर्ट

उज्जैन-सागर संभाग भी भीगेंगे; एमपी में अब तक कोटे से 10 फीसदी बारिश ज्यादा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। पूरे प्रदेश में सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हो रही है। बुधवार को प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। इस वजह से हालात भी बिगड़

मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, राजगढ़, आगर-मालवा और रतलाम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नीमच, उज्जैन, शाजापुर, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर और पन्ना में भारी बारिश का

इंदौर, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरंगा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में पानी गिरेगा।

टीकमगढ़ में घुटनों तक पानी में निकली आदिवासी बेटे की डोली- टीकमगढ़ जिले में बारिश के बाद बदहाल सड़कें लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं। जतारा जनपद की ग्राम पंचायत बैरवार में खराब सड़क और जलभराव के बीच एक आदिवासी बेटे की विदाई घुटनों तक पानी से होकर कराना पड़ी।

टीकमगढ़ जिले की बैरवार ग्राम पंचायत में खराब सड़क और जलभराव के बीच एक आदिवासी बेटे की विदाई घुटनों तक पानी से होकर कराना पड़ी।

वहीं सुभाष पुरम कॉलोनी में निर्माणाधीन अंडरग्राउंड नाले के कारण बड़ा हादसा हो गया। पाइपलाइन निर्माण के दौरान बनाए गए चेंबर बारिश के पानी में डूब गए थे।



गाए। कई रास्ते बंद हुए हैं और जनजीवन खासा प्रभावित रहा।

मौसम विभाग ने भिंड में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं,

अनुमान है। यानी, प्रदेश का उत्तरी हिस्सा अगले 24 घंटे के दौरान तरबतर रहेगा।

आज भोपाल समेत कई जगह बारिश- भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़,

शाजापुर में नाला पार कर स्कूल पहुंचे टीचर

इससे पहले बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में नदी-नाले उफान पर रहे। संध्या में ग्रामीण अंचलों के नदी-नाले उफान पर होने से जनजीवन प्रभावित रहा। शाजापुर में टीचर जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते नजर आए। रतलाम में अंडर ब्रिज पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार, दमोह में पौने 2 इंच, नर्मदापुरम में 1.1 इंच, खजुराहो-टीकमगढ़ में पौन इंच, जबलपुर, खरगोन-बैतूल में आधा इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। दतिया, धार, ग्वालियर, खंडवा, रतलाम, श्योपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, मंडला, नरसिंहपुर, नौगांव, सागर, सतना, सिवनी, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, पन्ना, बड़वानी, देवास, सीहोर में भी बारिश हुई। बारिश की वजह से दिन के तापमान में गिरावट देखी गई। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में इंदौर में सबसे कम 28 डिग्री, जबलपुर में 28.5 डिग्री, उज्जैन में 29.2 डिग्री, ग्वालियर में 29.7 डिग्री और भोपाल में 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान सीधी में 33.6 डिग्री और सबसे कम छिंदवाड़ा में 25.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

महिलाओं और बच्चों की डिजिटल और साइबर सुरक्षा पर दिया जोर

महिला आयोग और गूगल एक मंच पर



भोपाल (नप्र)। डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा आज देश के सामने सबसे बड़ी सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों में शामिल हो गई है। इसी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, एनजीओ और गूगल के सहयोग से भोपाल में आयोजित विशेष एनजीओ मीट में डिजिटल सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग पर व्यापक विमर्श हुआ।

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की सदस्य श्रीमती साधना स्थापक ने कहा कि डिजिटल युग ने जितने अवसर उपलब्ध कराए हैं, उतनी ही नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा केवल कानून या तकनीक का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की बदलती प्रकृति को देखते हुए डिजिटल जागरूकता, समय पर शिकायत और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को जन-आंदोलन का स्वरूप देना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग सिखाना समय की आवश्यकता है। परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और शासन के समन्वित प्रयासों से ही ऐसा डिजिटल वातावरण बनाया जा सकता है, जहां प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे।

कार्यक्रम में आयोग के सदस्य सचिव सुरेश तोमर भी उपस्थित रहे। 'रिस्पॉन्सिबल नेटिजन' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित संवाद में महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं ने भाग लेकर जमीनी अनुभव साझा किए। वहीं दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के भोपाल स्थित शासकीय निवास पर गूगल और एनजीओ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की।